www.avadhkaawaz.com

अवध की आवाज

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक समाचार पत्र राजधानी लखनऊ उत्तर प्रदेश से प्रकाशित

वर्ष–10 अंक–112 R.N.I.- UPHIN/2012/45127 लखनऊ शनिवार 24 जुलाई 2021 पृष्ठ – 8 मूल्य–3 रूपया

उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने 89053.22 लाख रूपए की 291 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण

अवध की आवाज

लखनऊ। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य ने वर्चुअल माध्यम से सहारनपुर क्षेत्र के अन्तर्गत 89053.22 लाख

रूपये की 291 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होने अधिकारियों को निर्देश दिए कि औपचारिक रूप से एक माह के भीतर स्थानीय स्तर पर इन परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में कराया जाए। उन्होंने कहा कि कार्य में गुणवत्ता तथा शीघ्रता से कार्य पूरा कर जनता को सुविधा दी जाए। उन्होने कहा कि आज प्रदेश और देश में चारो तरफ विकास की गंगा बह रही है। उन्होने कहा कि जनता की सुरक्षा एवं विकास से संबंधित जितनी डिमाण्ड मेरे पास आई है। मैं उन सबको स्वीकार करता हूँ। उन्होने यमुना नदी पर हरियाणा से जोडने के लिए सौंधेबांस गांव में पुल निर्माण को भी स्वीकृति दी। उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य ने आज से वर्चुअल विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यस किया। उन्होंने इस अवसर पर समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान सरकार गुण्डाराज और भ्रष्टाचार को खत्म कर सबका साथ–सबका विकास तथा सबका विश्वास के मंत्र के साथ कार्य कर रही है। उन्होने कहा कि उत्तर प्रदेश के अन्दर गरीब कल्याण, किसान कल्याण तथा विकास योजनाओं में भ्रष्टाचार करने वालों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी। उन्होने कहा कि वर्तमान सरकार का मतलब भ्रष्टाचार मुक्त, सरकार तथा गरीबों और किसानों का विकास है। उन्होने कहा कि अधिकारी जनहित के कार्यों तथा जन प्रतिनिधियों और जनता की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित करें। उन्होने कहा कि वर्तमान सरकार में जितना पैसा केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा भेजा जाता है उतना पैसा लाभार्थी को मिलता है। उन्होने कहा कि हमारा लक्ष्य उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता का विकास तथा उनके जीवन में खुशहाली लाना है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि वर्तमान सरकार ने प्रत्येक नागरिक को सम्मान देने का कार्य किया है। उन्होने कहा कि वर्तमान सरकार का लक्ष्य विकास, गरीबों का उत्थान, बेरोजगार को रोजगार, किसान की आमदनी बढाने के साथ बेहतर शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। स्कूल टॉपर बच्चों के घरों और विद्यालयों तक सड़घ्क, शहीदों के घरों तक सड़क, खिलाडियों के घरों तक सड़क बनाने का कार्य करने के साथ ही विभिन्न जन कल्याणकारी कार्य वर्तमान सरकार कर रही है। इस अवसर पर आयुष मंत्री डॉ0 धर्म सिंह सैनी, पिछडा वर्ग आयोग के अध्यक्ष श्री जसवंत सिह सैनी, विधायक श्री देवेन्द्र निम, कुवंर बृजेश सिंह, श्री किरत सिंह, महापौर श्री संजीव वालिया, श्री महेन्द्र सैनी, श्री राकेश जैन, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री मांगेराम चौधरी, पूर्व सांसद राघव लखनपाल शर्मा तथा अन्य जनप्रतिनिधिगण और लोक निर्माण विभाग के अधिकारीगण उपस्थित रहे।

4050 बच्चों के खाते में सीएम ने भेजे 12-12 हजार, अनाथ बच्चों के बाद अब निराश्रित महिलाओं के लिए भी योजना

अवध की आवाज

लखनऊ। कोरोना संक्रमण के चलते अपने मां–बाप या अभिभावक को खोने वाले अनाथ बच्चों के लालन–पालन के उद्देश्य से राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बृहस्पतिवार को 'मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना' का शुभारंभ किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने योजना के तहत प्रदेश भर से चिन्हीत 4050 अनाथ बच्चों के अभिभावकों को बैंक खाते में प्रतिमाह 4 हजार रुपये के हिसाब से तीन महीने का 12–12 हजार रुपये भी ट्रांसफर किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कोरोना काल में निराश्रित हुई महिलाओं के लिए भी एक नई योजना शुरू करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कोरोना के अलावा दूसरी बीमारियों से भी जो बच्चे अनाथ हुए हैं उन्हें भी योजना में शामिल करने की घोषणा की।

लोकभवन में महिला कल्याण विभाग की ओर से आयोजित कार्यक्रम में योजना का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मार्च 2020 में प्रदेश में जब कोरोना का पहला केस आया था तब हमारे पास जांच की कोई सुविधा नहीं थी। हमने जांच का नमूना एनआइवी पुणे भेजा था। आज उत्तर प्रदेश चार लाख टेस्ट प्रतिदिन करने की क्षमता रखता है। इसके लिए नई प्रयोगशालाएं व इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए गए। डेढ़ लाख बेड अस्पतालों में मौजूद हैं। महामारी से जूझने के लिए सरकार ने हर संभव प्रयास किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कोरोना काल में 240 बच्चों ने अपने माता–पिता दोनों को खो दिया जबकि 3810 बच्चों ने माता या पिता दोनों में से एक को खोया है। इन बच्चों के लालन–पालन शिक्षा व स्वास्थ्य की चिंता अब राज्य सरकार करेगी। उन्होंने कहा कि ऐसे बच्चे जिनका पालन–पोषण उनके स्वजन नहीं कर सकते हैं उन्हें बाल गृहों में रखा जाएगा। प्रत्येक मंडल मुख्यालय पर अटल आवासीय विद्यालय बन रहे हैं, इनमें बच्चों को पढ़ाया जाएगा। बालिकाओं को कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों में शिक्षा प्रदान की जाएगी। उन्होंने बताया कि निराश्रित बच्चों के लिए पीएम केयर्स के दिशा–निर्देश जल्द आने वाले हैं, इसका लाभ भी बच्चों को दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम सभी जानते हैं पूरी दुनिया बीते 17 महीने से इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना से जूझ रही है। इस दौरान प्रदेश में जो आंकड़े सामने आए हैं। जो बच्चे अनाथ हुए हैं उनको लाभान्वित किया गया है। ऐसे बच्चे जिनके माता–पिता या वैध अभिभावक नहीं हैं तो उन्हें बाल संरक्षण गृह में रखा गया है। इसके बाद इनको हर कमिश्नरी मुख्यालय में हमारे 18 अटल आवासीय विद्यालय में रखा जाएगा। यहां हम प्रदेश के उन सभी बच्चों को लेकर आने वाले हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम आज पहले तीन महीने का मानदेय यानी हर बच्चे को 12.12 हजार रुपये हर माह उपलब्ध करा रहे हैं। 18 वर्ष की उम्र तक राज्य सरकार उनके लालन–पालन की व्यवस्था करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इतना ही नहीं, मार्च 2020 के बाद भी अगर कोई महिला निराश्रित हुई है और पति या अभिभावक को खो दी है तो उस महिला को भी एक नई स्कीम के साथ जोड़कर शासन की योजनाओं से आच्छादित करने का हमने फैसला किया है। इसके लिए राज्य सरकार एक नई स्कीम लेकर आने वाली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस से प्रभावित बच्चों के सहयोग व सशक्तीकरण के लिए पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना की घोषणा की है। इस बारे में विस्तृत दिशा–निर्देश शीघ्र आने वाले हैं। पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन के सहयोग से भी हम बच्चों को आच्छादित करने की कार्ययोजना को आगे बढ़ा पाएंगे। इस मौके पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने 10 लाभार्थी बच्चों को प्रतीकात्मक रुप से स्वीकृति पत्र, स्कूल बैग, चाकलेट दिया। इनमें से दो बच्चों को टैब भी दिए गए।

लोक भवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देते हुए साथ में बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी

मेदान्ता हॉस्पिटल में आज से किया स्ट्रोक क्लीनिक का शुभारंभ

श्याम कुमार यादव

गोसाईंगंज, लखनऊ। मेदांता लखनऊ स्ट्रोक क्लिनिक का शुभारम्भ 23 जुलाई 2021 को मेदांता अस्पताल लखनऊ में एक नए स्ट्रोक क्लिनिक का उद्घाटन किया गया। जिसका उद्देश्य स्ट्रोक के रोगियों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं और सेवाओं में सुधार करना था। डॉ ऋत्विज बिहारी एसोसिएट डायरेक्टर न्यूरोलॉजीने स्ट्रोक के बारे में बताया की भारत में स्ट्रोक का बोझ प्रति वर्ष 1.5 मिलियन से अधिक स्ट्रोक के मामलों के साथ बहुत अधिक है।जो पश्चिमी औद्योगिक देशों की तुलना में बहुत अधिक है और टेनेक्टिप्लेस एकमात्र स्वीकृत घोम्बोलाइटिक एजेंट हैं जो वर्तमान में स्ट्रोक की शुरुआत से 4. 5 घंटे के ग्रोम्बोलिसिस ने एक्यूट स्ट्रोक के प्रबंधन में बड़े बदलाव के लिए उत्प्रेरक का काम किया है। इंट्रावेनस अल्टेप्लेस स्ट्रोक भारत में मृत्यु का स्थायी विकलांगता का सबसे आम कारण है भीतर तीव्र इस्केमिक स्टोक के लिए सांकेतित हैं। बहरहाल समय मस्तिष्क है और शोम्बोलिसिस में समय की देरी को कम करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए। तीव्र इस्केमिक स्ट्रोक का सबसे प्रभावी उपचार होने के बावजूद। दुनिया भर में अंबोलाइसिस की दर सभी स्ट्रोक का मुश्किल से 1–3 : है। डॉ संजय टंडन (माननीय सचिव यूपी एपीआई , अध्यक्ष चुने गए लखनऊ एपीआई) और डॉ ए के पांडे (एचओडी न्यूरोलॉजी, विवेकानंद पॉलीक्लिनिक लखनऊ) ने स्ट्रोक क्लिनिक का उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह में डॉ राकेश कपूर, निदेशक मेदांता लखनऊ और अन्य वरिष्ठ चिकित्सक सहित स्वास्थ्य कर्मचारी, मरीज और उनके रिश्तेदार मौजूद थे. स्ट्रोक क्लिनिक निदान , उपचार, जीवन शैली में मदद करके स्ट्रोक वाले सभी रोगियों का व्यापक, बहु – विषयक और किफायती प्रबंधन प्रदान करेगा। मेदांता लखनऊ के न्यूरोलॉजी विभाग के डायरेक्टर डॉ अनूप ठक्कर डॉ सुधाकर पांडेय कंसलटेंट डॉ प्रदीप एसोसिएट कंसलटेंट तथा न्यूरोसर्जरी विभाग के डायरेक्टर डॉ रवि शंकर, एसोसिएट डायरेक्टर डॉ प्रमोद चौरसिया , कंसलटेंट डॉ सतीश , कंसलटेंट न्यूरो इंटरवेंशन डॉ रोहित अग्रवाल और इमरजेंसी हेड कंसलटेंट डॉ लोकेन्द्र गुप्ता भी इस आयोजन में सम्मलित हुए।

महिला ने फाँसी लगाकर की जीवन लीला समाप्त

उन्नाव। गंगाघाट कोतवाली के अंतर्गत शुक्लागंज में कंचन नगर बी प्राइमरी स्कूल के पास महिला ने लगाई फांसी शिखा तिवारी उम्र लगभग 38 वर्ष ने लगाई फांसी घर में आपसी विवाद को लेकर शिखा तिवारी पति सोनू तिवारी व शिखा तिवारी के

दो बेटे हैं आदित्य तिवारी 1 दूसरे का नाम कृष्णा तिवारी है आपसी विवाद को लेकर शिखा तिवारी ने लगाई फांसी दोनों बच्चों वा पती का है रो रो कर बुरा हाल गंगा घाट प्रशासन मौके पर रहा मौजूद।

काम करने का तरीका होगा अलग,पूर्ण जिम्मेदारी से करें काम–खण्ड विकास अधिकारी राकेश सिंह

निघासन खीरी।

बीते दिनों हुये तबादले मे विकासखंड मे तैनात बीडियो

अलोक वर्मा का तबादला बाराबंकी हो जाने से पसगंवा ब्लॉक में कार्यरत खंडविकास अधिकारी राकेश कुमार सिंह का स्थानांतरण निघासन ब्लाक में हुआ कार्यभार संभालते ही राकेश कुमार सिंह ने बताया की प्राचीन बनी इमारतों का सौंदर्यीकरण कराना वह उन्हें एक अलग ही रूप देना किसी भी देशभक्तों की कहीं पर बनी इस प्रतिमा का सुंदरीकरण कराना।कई अलग जगह प्रतिभा का स्थापना करना उनके द्वारा बताया गया कि हम ब्लॉक में एक अलग ही तरीके से काम करना चाह रहे हैं।जिसमे आप सभी का साथ और पूर्णनिष्ठा से काम करें जिससे कार्य बेहतर हो सके।

हाईकोर्ट चौराहा स्थित सच को दिखाते मीडिया संस्थानों पर सरकारी छापे और तानाशाही के विरोध में प्रदर्शन करते आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता

अवध की आवाज ब्यूरो

राष्ट्रीय महिला आयोग एवं उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग के संयुक्त तत्वाधान में एक दिवसीय विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन कार्यक्रम में अध्यक्षता करते हुए माननीय सदस्या, उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग, मनोरमा शुक्ला जी व जिलाधिकारी महोदय रविंद्र कुमार।

राष्ट्रीय महिला आयोग एवं उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग के संयुक्त तत्वाधान में एक दिवसीय विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन कार्यक्रम में अध्यक्षता करते हुए माननीय सदस्या, उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग, श्रीमती मनोरमा शुक्ला जी व जिलाधिकारी महोदय श्री रविंद्र कुमार।

मड़ियाव थाना क्षेत्र अंतर्गत हाईटेक घैला पुलिस चौकी का हुआ जीर्णोद्धार के बाद उद्घाटन

लखनऊ। पुलिस और स्थानीय जन सहयोग से यह आलीशान पुलिस चौकी बनाई गई है। तत्कालीन सब इंस्पेक्टर विनोद कुमार सिंह

के प्रयास से वर्तमान में तैनात सब इंस्पेक्टर चंद्रकांत यादव ने इंस्पेक्टर मड़ियाव मनोज कुमार सिंह के सहयोग से पुलिस चौकी का संपूर्ण विकास कार्य कराया । अपराध पर लगाम लगाने के लिए इस हाईटेक पुलिस चौकी के चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे लगवाए गए हैं । अपराधियों के किसी भी अपराधिक गतिविधियों को यह कैमरे कैद करेंगे।इस दौरान एडीसीपी ने रिबन काटकर पुलिस चौकी का उद्घाटन किया । इस दौरान डीसीपी नॉर्थ देवेश कुमार पांडे, एडीसीपी प्राची सिंह , एसीपी अलीगंज अखिलेश सिंह, इंस्पेक्टर अलीगंज पन्नालाल यादव, इंस्पेक्टर मड़ियाव मनोज कुमार सिंह रहे मौजूद रहे।

शुभेंदु अधिकारी ने आपराधिक मामले सीबीआई को सौंपने के लिए अदालत में याचिका की दायर

कोलकाता, (वेबवार्ता)। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता एवं भाजपा विधायक शुभेंदु अधिकारी ने ''राजनीतिक प्रतिशोध'' का आरोप लगाते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की है और राज्य की पुलिस द्वारा अपने खिलाफ दर्ज किए गए सभी आपराधिक मामलों को सीबीआई को सौंपने का अनुरोध किया है।

अधिकारी ने राज्य पुलिस द्वारा उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकियों को भी रद्द करने का आदेश देने का आग्रह किया है। भाजपा विधायक ने अपने खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों को ''निष्पक्ष जांच'' के लिए सीबीआई को सौंपने का अनुरोध करते हुए बृहस्पतिवार को रिट याचिका दायर की।

उन्होंने आरोप लगाया है कि विपक्षी दल का नेता होने के कारण उन्हें ''राजनीतिक प्रतिशोध'' का सामना करना पड़ रहा है और उनके खिलाफ ''झूठे दावे'' करके मामले दर्ज किए गए। उन्होंने उच्च न्यायालय से उनके खिलाफ प्राथमिकियों को रद्द करने का निर्देश देने का भी अनुरोध किया। राज्य की पुलिस और आपराधिक जांच विभाग (सीआईडी) अधिकारी से जुड़े कई मामलों की जांच कर रहा है।

पेगासस जासूसी सॉफ्टवेयर के साथ कथित जासूसी गतिविधियों को लेकर देशभर में मचे हंगामे के बीच भाजपा नेता ने यह कहकर विवाद खड़ा कर दिया कि उन्हें पूर्व मेदिनीपुर जिले के पुलिस अधीक्षक अमरनाथ के. की फोन से जुड़ी जानकारियां मिली थीं जिसके चलते पुलिस ने मंगलवार को उनके खिलाफ स्वतः संज्ञान मामला दायर किया।

अधिकारी ने सोमवार को जिले के तमलुक इलाके में पार्टी की एक बैठक के दौरान स्थानीय पुलिस प्रमुख को सार्वजनिक रूप से सलाह दी थी कि वह ''ऐसा कुछ भी न करें जिससे उनका कश्मीर में तबादला करना पड़ जाए। नंदीग्राम से विधायक अधिकारी ने इस साल की शुरुआत में हुए विधानसभा चुनावों में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को मामूली अंतर से हराया। जिला पुलिस पूर्व मेदिनीपुर में राहत सामग्री की कथित चोरी के मामले की भी जांच कर रही है। राज्य सीआईडी एक पुलिस कांस्टेबल की अप्राकृतिक मौत की जांच कर रही है जो तीन साल पहले अधिकारी के सुरक्षा दल का हिस्सा था जब वह पूर्ववर्ती टीएमसी सरकार में मंत्री थे। कांस्टेबल की विधवा की शिकायत पर हाल में हत्या का मामला दर्ज किया गया और मामले की जांच सीआईडी को सौंपी गयी।

शांतनु सेन मानूसन सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित, रास में तृणमूल सदस्यों का हंगामा

नई दिल्ली,(वेबवार्ता)। तृणमूल कांग्रेस सदस्य शांतनु सेन को सदन में उनके अशोभनीय आचरण के लिए शुक्रवार को राज्यसभा के मौजूदा सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित कर दिया गया। इसके बाद तृणमूल एवं अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों के हंगामे के कारण संसद में व्यवधान पैदा हुआ। लिहाजा दो बार के स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही दोपहर ढाई बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। सुबह सदन की कार्यवाही आरंभ होते ही दो दिवंगत सांसदों को श्रद्धांजलि दी गई और कुछ विधायी कामकाज निपटाने के बाद सभापति एम वेंकैया नायडू ने इस पर गहरा क्षोभ व्यक्त किया कि संसद का मानसून सत्र शुरू होने के बाद अब तक केवल कोविड–19 महामारी के मुद्दे पर चार घंटे की चर्चा हो पाई है और इसके अलावा कोई अन्य कामकाज हंगामे की वजह से नहीं हो पाया। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी की विभीषिका के बीच यह सत्र आयोजित हुआ है और जनता से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जानी है। सभापति ने बृहस्पतिवार को सदन में हुए हंगामे और इस दौरान शांतनु सेन सहित अन्य विपक्षी नेताओं के आचरण का जिक्र किया और इसे अशोभनीय बताया। सभापति ने कहा कि कल जो कुछ हुआ, निश्चित रूप से उससे सदन की गरिमा प्रभावित हुई। गौरतलब है कि सेन ने बृहस्पतिवार को केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के हाथों से ''पैगासस विवाद'' संबंधी बयान की प्रति छीन ली थी और उसके टुकड़े कर हवा में लहरा दी थी। संसदीय कार्य राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने कल की घटना को लेकर शांतनु सेन को सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित किए जाने का प्रस्ताव रखा। इसके बाद नायडू ने सेन को सत्र की शेष अवधि से निलंबित किए जाने की घोषणा की। तृणमूल कांग्रेस के सदस्य शुखेंदु शेखर रॉय ने कहा कि मुरलीधरन ने अचानक से सेन के निलंबन का प्रस्ताव पेश कर दिया लेकिन सदन में आज की कार्यसूची में इसका कोई उल्लेख नहीं था। सभापति ने उनकी आपत्ति को खारिज कर दिया। कांग्रेस के सदस्य जयराम रमेश भी इस मुद्दे पर कुछ बोल रहे थे लेकिन हंगामे की वजह से उनकी बात नहीं सुनी जा सकी। इसी बीच, तृणमूल कांग्रेस सदस्यों ने हंगामा तेज कर दिया। इस दौरान नायडू ने सेन को सदन से बाहर जाने को कहा लेकिन वह अपनी सीट पर बैठे रहे। तृणमूल कांग्रेस के सदस्यों ने सेन के निलंबन की घोषणा पर आपत्ति जताते हुए हंगामा तेज कर दिया। सभापति ने सदस्यों से शांत रहने और कामकाज चलने देने की अपील की। लेकिन सदन में व्यवस्था बनते न देख उन्होंने बैठक को 11 बज कर करीब 25 मिनट पर दोपहर बारह बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। जैसे ही दोपहर 12 बजे सदन की कार्यवाही आरंभ हुई, उपसभापति हरिवंश ने निलंबित सदस्य शांतनु सेन को यह कहते हुए सदन से बाहर जाने को कहा कि उनके निलंबन का प्रस्ताव मंजूर कर लिया गया है। उन्होंने कहा, ''कृपया आप सदन से बाहर चले जाएं। इसी समय तृणमूल कांग्रेस के सदस्यों ने हंगामा आरंभ कर दिया। लिहाजा, उपसभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12.30 बजे तक स्थगित कर दी गई। इसके बाद जब सदन की कार्यवाही आरंभ हुई तो सदन की स्थिति ज्यों की त्यों बनी रही। सेन सदन में मौजूद थे। उपसभापति ने सेन से बार–बार आग्रह किया कि उनके खिलाफ निलंबन का प्रस्ताव मंजूर किया जा चुका है लिहाजा वह सदन से बाहर चले जाएं। जब ऐसा नहीं हुआ तो उपसभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर ढाई बजे तक के लिए स्थगित कर दी। इससे पहले, हंगामे के कारण सदन में आज भी शून्यकाल और प्रश्नकाल नहीं हो सके।

डाटा संरक्षण विधेयक पर संयुक्तसमिति का कार्यकाल पांचवी बार बढ़ाया गया

नई दिल्ली, (वेबवार्ता)। वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक, 2019 का अध्ययन कर रही संसद की संयुक्त समिति का कार्यकाल पांचवी बार बढ़ाया गया और अब समिति को रिपोर्ट जमा करने के लिए संसद के शीतकालीन सत्र के प्रथम सप्ताह तक का समय दिया गया है। भाजपा के पी. पी. चौधरी ने लोकसभा में इस संबंध में प्रस्ताव रखा जिसे सदन ने ध्वनिमत से स्वीकार कर लिया। प्रस्ताव में कहा गया है, यह सदन वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक, 2019 पर संसद की संयुक्त समिति को रिपोर्ट पेश करने के लिये समय को शीतकालीन सत्र के प्रथम सप्ताह तक बढ़ाता है । विधेयक का अध्ययन करने के लिए दिसंबर, 2019 में संसद की संयुक्त समिति का गठन किया गया था और उसे गत बजट सत्र में रिपोर्ट देनी थी, लेकिन तब समिति के लिए रिपोर्ट जमा करने की समय–सीमा संसद के मॉनसून सत्र के पहले सप्ताह तक बढ़ाई गयी थी। विधेयक में किसी व्यक्ति के निजी डाटा के सरकार और निजी कंपनियों द्वारा उपयोग के नियमन के प्रावधान हैं।

गुजरात में शुक्राणु देने के एक दिन बाद कोविड–19 मरीज की मौत

अहमदाबाद, (वेबवार्ता)। गुजरात में वडोदरा के एक निजी अस्पताल ने एक दिन पहले कोविड–19 से संक्रमित जिस व्यक्ति के शुक्राणु एकत्रित किए थे उसकी मौत हो गयी। अस्पताल ने व्यक्ति की पत्नी द्वारा दायर याचिका पर गुजरात उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार कोविड–19 मरीज के शुक्राणु एकत्रित किए थे। इस व्यक्ति की पत्नी के वकील ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। कोरोना वायरस से संक्रमित हो जाने के बाद कई अंगों के काम न करने के कारण 32 वर्षीय व्यक्ति को स्टर्लिंग अस्पताल में जीवन रक्षक प्रणाली पर रखा गया था। महिला के वकील निलय पटेल ने कहा, ''अस्पताल ने हमें सूचित किया कि उन्होंने मंगलवार शाम को उच्च न्यायालय के अनुमति देने के बाद मेरी मुवक्किल के पति के शुक्राणु ले लिए हैं। लेकिन बृहस्पतिवार को उनकी मौत हो गयी। मामले पर अगली सुनवाई आज होनी है। मरीज की पत्नी ने मंगलवार को उच्च न्यायालय का रुख करते हुए कहा था कि वह चाहती है कि उनका बच्चा आईवीएफ के जरिए हो लेकिन उसका पति अपने शुक्राणु लिए जाने की मंजूरी देने की स्थिति में नहीं है। महिला ने अदालत को बताया था कि डॉक्टरों के अनुसार उसके पति के बचने की उम्मीद बहुत कम है। अस्पताल ने आईवीएफ के लिए शुक्राणु लेने के लिए अदालत से आदेश लाने की मांग की थी जिसके बाद महिला ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। महिला की याचिका पर तत्काल सुनवाई करते हुए न्यायाधीश आशुतोष जे शास्त्री ने अस्पताल को जल्द से जल्द व्यक्ति का शुक्राणु लेने और उसे उचित तरीके से रखने का निर्देश दिया था। स्टर्लिंग अस्पताल के जोनल निदेशक अनिल नाम्बियार ने बुधवार को पत्रकारों को बताया कि डॉक्टरों ने अदालत का आदेश मिलने के कुछ घंटों के भीतर मंगलवार रात को मरीज का शुक्राणु सफलतापूर्वक ले लिया। आईवीएफ एआरटी के लिए मंजूरी देने पर अदालत की सुनवाई शुक्रवार को होनी है।

तेलंगाना में भारी बारिश से कई निचले इलाके जलमग्न

हैदराबाद, (वेबवार्ता)। तेलंगाना में पिछले दो दिन से हो रही बारिश के चलते शुक्रवार को कई निचले इलाके जलमग्न हो गए और सड़क संपर्क प्रभावित रहा। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि निर्मल तथा अन्य जिलों में राहत अभियान शुरू किया गया है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) के जवानों ने निजामाबाद जिले के एक आश्रम में फंसे सात लोगों के समूह को बचाया। उन्होंने बताया कि राज्य के सड़क एवं भवन मंत्री वेमुला प्रशांत रेड्डी ने अभियान की निगरानी की। आश्रम में फंसे लोगों को शुक्रवार तड़के बचाया गया। राज्य की महिला एवं बाल कल्याण मंत्री सत्यवती राठौड़ ने शुक्रवार को महबूबाबाद के जिला अधिकारियों के साथ बैठक की और जलाशय व अन्य जलस्रोत अपने बंध न तोड़ें इसके लिये इंतजाम करने के निर्देश दिये। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि कुमुराम भीम आसिफाबाद जिले के वनकिडी में 39 सेंटीमीटर बारिश हुई, इसके बाद आसिफाबाद में (30 सेंटीमीटर) ,निर्मल जिले के सारंगपुर में (21 सेंटीमीटर) बारिश हुई। उन्होंने बताया कि जगतियाल, निर्मल, निजामाबाद और वारंगल ग्रामीण में कई इलाकों में बहुत अधिक बारिश हुई। तेलंगाना में लगातार दूसरे दिन बारिश होने से बृहस्पतिवार को सामान्य जीवन प्रभावित रहा ,बारिश के कारण निचले इलाकों में पानी भर गया और सड़क संपर्क बाधित हो गया। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने बारिश से पैदा हुए हालात पर अधिकारियों के साथ बृहस्पतिवार को बैठक की और उन्हें सतर्क रहने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को बारिश से कठिनाई का सामना न करना पड़े।

छेड़खानी का वांछित अभियुक्त गिरफ्ता

अवध की आवाज ब्यूरो

उन्नाव। थाना फतेहपुर चौरासी, जनपद उन्नाव पुलिस अधीक्षक महोदय के कुशल निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक उन्नाव अधिकारी सफीपुर के कुशल पर्यवेक्षण में महिला संबन्धी अपराधों की रोकथाम एवं संबन्धित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना फतेहपुर चौरासी पुलिस द्वारा छेड़खानी के वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है।

पेगासस मामले की जांच की मांग को लेकर कांग्रेस ने संसद परिसर में प्रदर्शन किया

नई दिल्ली, (वेबवार्ता)। कांग्रेस के सांसदों ने पेगासस स्पाइवेयर का उपयोग करके राहुल गांधी समेत कई प्रमुख व्यक्तियों की कथित तौर पर जासूसी किए जाने के मामले की उच्चतम न्यायालय की निगरानी में न्यायिक जांच की मांग करते हुए शुक्रवार को संसद परिसर में प्रदर्शन किया।

लोकसभा और राज्यसभा के कई कांग्रेस सदस्यों ने संसद परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष प्रदर्शन किया।

कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी और कांग्रेस के कई अन्य सांसद इस मौके पर मौजूद थे।

उन्होंने अपने हाथ में एक बड़ा बैनर ले रखा था जिस पर 'वी डिमांड सुप्रीम कोर्ट मॉनीटर्ड ज्यूडिसियल प्रोब' (हम उच्चतम न्यायालय की निगरानी में न्यायिक जांच की मांग करते हैं) लिखा हुआ था।

उन्होंने 'जासूसी बंद करो' और 'प्रधानमंत्री सदन में आओ' के नारे भी लगाए।

गौरतलब है कि मीडिया संस्थानों के अंतरराष्ट्रीय गठजोड़ ने दावा किया है कि केवल सरकारी एजेंसियों को ही बेचे जाने वाले इजराइल के जासूसी सॉफ्टवेयर के जरिए भारत के कुछ रसूखदार लोगों सहित बड़ी संख्या में कारोबारियों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के 300 से अधिक मोबाइल नंबर, हो सकता है कि हैक किए गए हों।

अब मृत्यु प्रमाणपत्र में कोरोना से मौत का हो रहा जिक्र, शासन के आदेश के बाद शुरू हुई व्यवस्था

वाराणसी। कोरोना काल में वाराणसी नगर निगम की ओर से जारी होने वाले मृत्यु प्रमाणपत्र में ऑक्सीजन की कमी से मौत का जिक्र नहीं है। पिछले दिनों शासन के आदेश के बाद अब प्रमाणपत्र में कोरोना का जिक्र किया जा रहा है। दूसरी लहर एक अप्रैल से शुरू हुई। अस्पतालों में बेड के लिए मारामारी रही। वहीं, ऑक्सीजन और रेमडेसिवर इंजेक्शन के लिए भी लोग परेशान रहे। लोगों को अस्पताल से लेकर सीएमओ और डीएम कार्यालय तक का चक्कर काटना पड़ना। सरकारी आंकड़ों में दूसरी लहर में जिले में केवल 773 मौतें हुई हैं जबकि हकीकत में मृतकों की संख्या कहीं अधिक है। सामान्य दिनों में नगर निगम की ओर से 450 से 500 मृत्यु प्रमाणपत्र हर महीने जारी किए जाते हैं। वहीं, मार्च में 729, अप्रैल में 887, मई में 2692, जून में 590 और जुलाई में अब तक 400 से अधिक मृत्यु प्रमाणपत्र जारी किए गए हैं।

नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. एनपी सिंह ने बताया कि पिछले दिनों मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने वालों की संख्या अधिक रही। इस समय सामान्य माहौल है। पांचों जोनल कार्यालय पर आवेदन किए जा रहे हैं। जांच के बाद प्रमाणपत्र दिया जा रहा है। इसमें ऑक्सीजन की कमी से मौत का जिक्र नहीं होता है।

<u>कार्डियक अरेस्ट मौत की मुख्य वजह</u>

कोरोना की दूसरी लहर पहली के मुकाबले ज्यादा प्रभावी थी। इसमें न केवल संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ बल्कि मौतों का ग्राफ भी तेजी से बढ़ा। तेजी से बढ़ती संख्या के बाद शासन ने डेथ ऑडिट का निर्णय लिया था। इसमें स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना से होने वाली मौतों में कार्डियक अरेस्ट सहित अन्य बीमारियों को वजह बताया है। आंकड़ों के हिसाब से दूसरी लहर में सबसे अधिक अप्रैल में जहां सर्वाधिक 42,740 मरीज मिले। वहीं, मई में 199 मरीजों ने जान गंवाई।

<u>अलग–अलग बीमारियों से मरीजों की मौत</u>

सीएमओ डॉ. वीबी सिंह ने कहा कि कोरोना काल में अस्पतालों में भर्ती मरीजों का हर संभव बेहतर इलाज किया गया। इस दौरान अलग–अलग बीमारियों से मरीजों की मौत हुई। फिलहाल इस महीने किसी मरीज की मौत नहीं हुई है। संभावित तीसरी लहर से निपटने के सभी इंतजाम है।

युवक ने फांसी लगाकर दी जान

औरैया। शहर के मोहल्ला गोविंद नगर में किराए के मकान में रह रहे युवक ने फांसी लगाकर जान दे दी।

बड़े भाई की सूचना पर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा।

मोहल्ला गोविंद नगर में ट्रक चालक आसू पुत्र सुरेश चंद्र सैनी किराए के मकान में रहते हैं। उनके साथ छोटा भाई हिमांशु (24) भी रहता था। आशू ट्रक चलाने गया था। बुधवार शाम को वह कमरे पर लौटा तो हिमांशु का शव रोशनदान से रस्सी के फंदे पर फांसी पर लटका मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा।

मौके पर पहुंची मृतक की नानी बसंती देवी ने बताया कि हिमांशु की मां की कुछ साल पहले मौत हो गई थी। उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली है। वह लड़कों को साथ रखता नहीं है। हिमांशु कोई काम नहीं करता है। उसके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। बुधवार दोपहर लगभग 12 बजे उनके (नानी) घर खाना खाने गया था। आज भी खाने के लिए उसका इंतजार कर रही थी। शाम को उसकी मौत की सूचना मिली।

अज्ञात वाहन की चपेट में आकर युवक की मौत

अयोध्या। रौनाही थाना क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग–28 के मकसूमगंज चौराहे पर खेत की ओर जाते समय एक युवक की अज्ञात वाहन की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने उसको जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। क्षेत्र के मंगलसी निवासी रंजीत (30) गुरुवार सुबह करीब पांच बजे घर से खेत के लिए निकला था। लखनऊ–अयोध्या हाईवे पर किसी अज्ञात वाहन की चपेट आकर गंभीर रूप से घायल हो गया। जब तक स्थानीय पुलिस अस्पताल लेकर पहुंची, उसकी मौत हो गई। रौनाही थाने के एसएसआई शमशाद ने बताया कि युवक को गंभीर चोट लग गयी थी। चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पोस्टमार्टम कराया जा रहा है।

पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की हालत जस की तस

लखनऊ, (वेबवार्ता)। संक्रमण की शिकायत के बाद लखनऊ के संजय गांधी परास्नातक आयुर्विज्ञान संस्थान (एसजीपीजीआई) में भर्ती कराए गए उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की हालत जस की तस बनी है और उन्हें जीवन रक्षक प्रणाली पर रखा गया है। एसजीपीजीआई की ओर से शुक्रवार को जारी किए गए स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार, कल्याण सिंह की हालत जस की तस बनी है। उन्हें जीवन रक्षक प्रणाली पर रखा गया है। क्रिटिकल केयर मेडिसिन, नेफ्रोलॉजी, न्यूरोलॉजी और एंडॉक्रिनलॉजी विभाग के वरिष्ठ चिकित्सक पूर्व मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। एसजीपीजीआई के निदेशक प्रोफेसर आर. के. धीमान भी नियमित रूप से उनके इलाज की निगरानी कर रहे हैं। गौरतलब है कि 89 वर्षीय कल्याण सिंह को गत चार जुलाई को संक्रमण और बेहाशी के कारण एसजीपीजीआई में भर्ती कराया गया था। इससे पहले उनका इलाज राम मनोहर लोहिया चिकित्सा संस्थान में चल रहा था।

राहुल गांधी को लगता है कि उनका फोन टैप हुआ है तो उसे जांच एजेंसियों को सौंपेः भाजपा

नई दिल्ली, (वेबवार्ता)। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने शुक्रवार को कहा कि पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को यदि लगता है कि उनका फोन टैप किया गया है तो उन्हें इसे (फोन) जांच एजेंसी को सौंप देना चाहिए। भाजपा प्रवक्ता राज्यवर्धन सिंह राठौर ने संसद भवन परिसर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए दावा किया कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने अवैध तरीके से किसी का भी फोन टैप नहीं किया है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों में जनता के द्वारा लगातार दो बार खारिज किए जाने के बाद कांग्रेस किसी न किसी बहाने संसद की कार्यवाही को बाधित करना चाहती है। राहुल गांधी ने इजरायली स्पाइवेयर पेगासस का उपयोग करके भारत के कई प्रमुख व्यक्तियों की कथित तौर पर जासूसी किए जाने को 'राजद्रोह' करार देते हुए कहा था कि गृह मंत्री अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका की उच्चतम न्यायालय की निगरानी में न्यायिक जांच होनी चाहिए। राठौर ने कहा कि राहुल गांधी को अपना फोन जांच एजेंसी को सौंप देना चाहिए और भारतीय दंड संहिता के तहत जांच होनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस देश का विकास बर्दाश्त नहीं कर सकती इसलिए कोई ना कोई बहाना बनाकर वह संसद की कार्यवाही बाधित कर रही है।

कुख्यात बदमाश उधम सिंह को पुलिस ने किया गिरफ्तार

मेरठ (वेबवार्ता)। उत्तर प्रदेश के मेरठ जनपद के सरधना थाना क्षेत्र के कस्बा करनावल के एक कुख्यात बदमाश उधम सिंह को पुलिस ने उसके घर से गिरफ्तार कर लिया है। एसएसपी प्रभाकर चौधरी ने बताया कि सरधना थाना क्षेत्र के कस्बा करनावल का कुख्यात बदमाश उधम सिंह 'डी–50' गिरोह का सरगना है। वह कुछ दिन पहले ही जेल से जमानत पर बाहर आया था। उस पर 65 से अधिक संगीन धाराओं में तहत मामले दर्ज हैं। पुलिस को सूत्रों से पता चला था कि उधम सिंह जेल से छुटने के बाद लोगों को धमका कर उनसे उगाही कर रहा थ। एसएसपी के अनुसार, पिछले दिनों उधम सिंह ने गांव के 'इंडियन बैंक' के कर्मचारियों को बैंक ना खोलने के लिए धमकाया और जान से मारने की धमकी दी थी। कुछ बैंककर्मियों को घर बुलाकर उनके साथ बदसलूकी भी की थी। पुलिस ने बैंक के प्रबंधक गौरव राजपूत की तहरीर पर रंगदारी मांगने, जान से मारने की धमकी देने, सरकारी कार्य में बाधा डालने की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया और बृहस्पतिवार को उधम सिंह को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद उसे अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। गौरतलब है कि उधम सिंह लंबे समय से जेल में ही था। करीब 10 दिन पहले बाराबंकी जेल से जमानत पर बाहर आया था।

बहराइच में अवैध संबंध के संदेह में पति ने की पत्नी की हत्या

बहराइच (वेबवार्ता)। बहराइच जिले के कोतवाली नानपारा के बंजरिया गांव के एक व्यक्ति ने कथित तौर पर अवैध संबंध के संदेह में अपनी पत्नी की गला रेतकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) अशोक कुमार ने शुक्रवार को बताया कि नानपारा कोतवाली क्षेत्र के बंजरिया गांव के राजेश सिंह ने बृहस्पतिवार रात करीब ढाई बजे अपनी पत्नी रीता (32) की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी। इस दौरान उसे रोकने की कोशिश करने पर उसने अपने भाई पर भी चाकू से हमला कर दिया।

उन्होंने बताया कि प्रारंभिक जांच में पता चला है कि आरोपी को संदेह था कि उसकी पत्नी के किसी के साथ अवैध संबंध हैं। मृतका के पिता की तहरीर पर आरोपी राजेश के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। घायल भाई का नानपारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज चल रहा है। मामले की जांच अभी जारी है।

सम्पादकीय

अब पढ़ाई में भी खेल आरक्षण खत्म

हिमाचल प्रदेश सरकार के शिक्षा विभाग के सचिव ने पिछले साल एक निर्देश पत्र, जो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय सहित सभी सरकारी व निजी विश्वविद्यालयों को भेजा है, इस पत्र में विभिन्न विद्याओं में दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों के लिए रोस्टर है। इस रोस्टर में खेलों व अन्य गतिविधियों के लिए मिलने वाला पांच–पांच प्रतिशत आरक्षण गायब है। यह हिमाचल प्रदेश के खिलाडियों के साथ कोरोना काल में बहुत बड़ा मजाक हो गया है। शिक्षा का मतलब पढ़ाई के साथ–साथ विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास है, मगर हम खेलों व अन्य गतिविधियों को दरकिनार कर अपने विद्यार्थियों को किस प्रकार की शिक्षा देने जा रहे हैं, यह सोचने का विषय है। अगर रट्टा लगाकर परीक्षा ही पास करनी है तो फिर शिक्षा संस्थानों की क्या जरूरत है। हिमाचल प्रदेश में महाविद्यालय व विश्वविद्यालयों में खेल विंग तो पहले ही नहीं थे, अब खेल आरक्षण भी खत्म कर हिमाचल सरकार विद्यार्थी युवाओं को क्या संदेश देना चाहती है। हिमाचल प्रदेश सरकार को चाहिए कि वह पढ़ाई में खेल आरक्षण जारी रखे तथा राज्य में अधिक से अधिक सुविधा व प्रतिभा के अनुसार खेल विंग खोले ताकि हिमाचल प्रदेश के विद्यार्थी खिलाडियों का भला हो सके। पंजाब ने एक समय खेल विंगों के माध्यम से खेलों में श्रेष्ठतम स्थान प्राप्त किया हुआ था।

प्रतिभा व सुविधा के अनुसार हिमाचल प्रदेश के विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों में भी सरकार खेल विंग खोलती है तो भविष्य में हिमाचल के खिलाड़ी राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के कई महाविद्यालयों के पास अंतरराष्ट्रीय स्तर का खेल ढांचा तैयार खड़ा यूं ही बेकार हो रहा है। इस कॉलम के माध्यम से पहले भी इस विषय पर बहुत बार लिखा जा चुका है, मगर सरकार का रवैया उदासीन रहा है। खेल विंगों के लिए सरकार को न तो खेल ढांचा खड़ा करना पड़ता है और न ही नया छात्रावास बनाना पड़ता है। केवल खेल विशेष का प्रशिक्षक और खिलाडिध्यों के लिए खुराक व रहने का प्रबंध करना होता है, जो आसानी से बहुत कम धन राशि खर्च करके हो सकता है। हिमाचल प्रदेश में विभिन्न खेलों का स्तर राज्य में खेल छात्रावासों के खुलने के बाद काफी सुधरा है। हिमाचल प्रदेश में स्कूली स्तर पर पपरोला में लड़कों के लिए बास्केटबॉल, सुंदरनगर व नादौन में लड़कों की हाकी, माजरा में लड़कियां के लिए हाकी में खेल छात्रावास चल रहे हैं। वॉलीबाल में स्कूली स्तर पर प्रशिक्षण का प्रबंध है। मतियाणा व रोहडू में लड़कों को तथा कोटखाई में लडकियों के लिए खेल छात्रावासों को वर्षों पहले से शुरू किया गया है। रोहडू में फुटबॉल का भी खेल छात्रावास है। इन छात्रावासों में अच्छे प्रशिक्षकों के साथ–साथ खेल सुविधाओं में काफी सुधार की जरूरत है, मगर महाविद्यालय व विश्वविद्यालय स्तर पर कोई भी खेल विंग अभी तक हिमाचल प्रदेश के खिलाड़ी विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध नहीं है। हिमाचल प्रदेश में भारतीय खेल प्राधिकरण ने तीस वर्ष पहले शिलारू में विशेष खेल क्षेत्र योजना के अंतर्गत खेल छात्रावास शुरू किया था जो राष्ट्रीय स्तर पर अच्छे परिणाम देने के बावजूद बंद हो गया था। उसी समय बिलासपुर व धर्मशाला में भारतीय खेल प्राधिकरण ने खेल छात्रावासों की शुरुआत की और ये आज तक चल रहे हैं और यहां से कुछ अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी भी निकल रहे हैं। मगर ये खेल छात्रावास हिमाचल प्रदेश के भूगोल को देखते हुए बहुत कम हैं। इसलिए हिमाचल प्रदेश के महाविद्यालयों व विश्वविद्यालयों में खेल विंगों की मांग बहुत पहले से हो रही है।

आज तक खेल विंग तो मिले नहीं, जो पढ़ाई में पांच प्रतिशत आरक्षण था, वह भी खत्म कर दिया। खिलाड़ी विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई के साथ–साथ दिन में कम से कम चार घंटे खेल प्रशिक्षण को देने पड़ते हैं तथा जिला स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक होने वाली खेल प्रतियोगिताओं व अंतर महाविद्यालय खेल प्रतियोगिता से लेकर अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय खेलों में भाग लेने के लिए महीनों कक्षा व संस्थान से दूर रहना पड़ता है। स्वाभाविक ही है कि आम विद्यार्थियों के मुकाबले खिलाड़ी विद्यार्थियों को पढ़ाई के लिए बहुत ही कम समय मिलता है। राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए कई वर्ष समाज से कट कर खिलाड़ी को कठिन परिश्रम करना पड़ता है। इस तरह वह पढ़ाई के साथ–साथ सामाजिक व आर्थिक रूप से भी पिछड़ जाता है। इसलिए ही उत्कृष्ट प्रदर्शन कर पदक विजेता खिलाडिध्यों को काफी विचार–विमर्श के बाद ही खेल आरक्षण दिया गया है। मगर हमारे प्रशासनिक अधिकारी तथा बुद्धिजीवी पता नहीं क्यों इस सत्य को नकार रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में खेल संस्कृति तैयार हो, इसके लिए राज्य में उपलब्ध सुविधाओं को आसानी से खिलाडियों को देना होगा। साथ ही साथ महाविद्यालय व विश्वविद्यालय स्तर पर बंद किए गए खेल आरक्षण को फिर से शुरू करना होगा। तभी हम हिमाचल में प्रशिक्षण करवा कर राष्ट्रीय स्तर पर हिमाचल प्रदेश के नाम को रोशन कर सकते हैं क्योंकि बेटा–बेटी तो हिमाचल का होगा, मगर उनके साथ हिमाचल प्रदेश का नाम नहीं होगा। वह अन्य राज्यों व विश्वविद्यालयों की ओर से खेलते नजर आएंगे। पहले तभी तो सुविधाओं के अभाव में हिमाचल प्रदेश के विद्यार्थी खिलाड़ी दूसरे राज्यों का रुख करते थे । आज जब अंतरराष्ट्रीय स्तर की खेल सुविधाएं बन कर तैयार हैं और हम पढ़ाई में खेल आरक्षण खत्म कर रहे हैं, ये हम अपनी आगामी पीढ़ी को क्या देने जा रहे हैं। हम कब तक हिमाचल प्रदेश से प्रतिभाओं का पलायन होते मूकदर्शक बनकर देखते रहेंगे।

ज्ञान का बोध कराती है गुरुकुल परंपरा

(लेखक- सुरेश हिन्दुस्तानी ईएमएस)

हम प्रायः सुनते हैं कि हमारा देश विश्व गुरु रहा है, विश्व गुरु याने सम्पूर्ण क्षेत्रों में विश्व का मार्ग दर्शन करने वाला, लेकिन क्या हमने सोचा है कि भारत का वह कौन सा गुण था, जिसके कारण विश्व के अंदर भारतीय प्रतिभा और क्षमता का बोलबाला था। इसका उत्तर आज भले ही कोई नहीं जानता हो, लेकिन यथार्थ यही है कि इसके पीछे मात्र भारतीय गुरुकुल ही थे। भारतीय संस्कृति में गुरुकुल शिक्षा प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है, जिसमें बालक के सम्पूर्ण विकास की अवधारणा और संरचना होती है। उस समय के हिसाब से गुरुकुलों में विश्व की सबसे श्रेष्ठ शिक्षा दी जाती थी। छात्रों का समग्र विकास किया जाता था। चाहे वह ज्ञान विज्ञान का क्षेत्र हो या शारीरिक शिक्षा की बात हो या फिर नैतिक और व्यावहारिक संस्कारों की ही बात हो। गुरुकुल की शिक्षा बहुमुखी प्रतिभा का विकास करती थी। आज देश में कई गुरुकुल चल रहे हैं, उसमें बहुत आश्चर्यजनक प्रतिभा संपन्न बालकों का निर्माण भी हो रहा है। पिछले समय गूगल बॉय के रुप में चर्चित होने वाला बालक इन्हीं गुरुकुलों की देन है। गुजरात के कर्णावती में हेमचंद्राचार्य गुरुकुल में ऐसे नन्हे प्रतिभाशाली छात्रों को देखकर विदेशी भी चकित हैं। हमारे देश को वास्तव में गुरुकुल आधारित शिक्षा पद्धति की आवश्यकता है, क्योंकि यही भारत की वास्तविक शिक्षा है और इसी से छात्रों का समग्र विकास हो सकता है।

शिक्षा प्रणाली का किसी भी देश के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान होता है। भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद जिस प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए थी, उसका हमारे देश में नितांत अभाव महसूस किया जाता रहा है। शायद, स्वतंत्रता मिलने के बाद हमारे नीति निर्धारकों ने शिक्षा नीति बनाने के बारे में कम चिन्तन किया। इसी कारण आज की नई पीढ़ी को इतिहास की जानकारी देने से वंचित किया जा रहा है। यहां यह बताना आवश्यक है कि इतिहास कोई सौ या दो सौ सालों में नहीं बनते। जहां तक भारत के दो सौ सालों के इतिहास की बात है तो इस दौरान भारत परतंत्रता की जंजीरों में जकड़ा रहा था। इसलिए स्वाभाविक है कि उस कालखंड का इतिहास हमारा मूल इतिहास नहीं कहा जा सकता। अगर हमें भारत के इतिहास का अध्ययन करना है तो उस कालखंड में जाना होगा, जब भारत पर किसी विदेशी का शासन नहीं था। क्या आज यह इतिहास कोई जानता है, ... बिलकुल नहीं।

मार्क्सवादी चिन्तक मैकाले ने शिक्षा के लिए जिस नीति को समाज के लिए प्रस्तुत किया, उसका हमारी सरकारों ने आंख बंद करके समर्थन किया, लेकिन इसके परिणाम क्या होंगे, इसका चिन्तन नहीं किया गया। नतीजतन, आज सरेआम कहीं–कहीं भारत माता को डायन कहने के स्वर सुनाई देते हैं, तो कहीं भारत तेरे टुकड़े होंगे बोलने वालों का जमावड़ा दिखाई देता है। आज जो वातावरण देश में दिखाई देता है, उससे यही अनुमान लगाया जा सकता है कि हम अपनी मूल धारा से विमुख होते दिखाई दे रहे हैं। हमें विदेशी गुलामी के बाद जिस प्रकार का भारत मिला, हमारी सरकारों ने वैसे ही स्वरुप में उसे स्वीकार कर लिया।

देश में अभी जो शिक्षा प्रदान की जा रही है, वह सांस्कृतिक मानकों के हिसाब से भारतीय नीति के अनुरूप नहीं कही जा सकती। विश्व के प्रायः सभी देशों में जो शिक्षा प्रदान की जाती है, वह उस देश के मूल भाव को संवर्धित करती हुई दिखाई देती है। इसके अलावा शिक्षा का मूल भी यही होना चाहिए कि उसमें उस देश का मूल संस्कार परिलक्षित हो। हमारे देश में किस प्रकार की शिक्षा प्रदान की जा रही है, इसका अध्ययन करने से पता चलता है कि जिन महापुरुषों ने देश की सुरक्षा को अपने कर्तव्य का मूल समझा था, आज वे महापुरुष राजनीति का शिकार होते जा रहे हैं। अंग्रेज जिनको सत्ता सौंप कर गए, उनका ही बोलबाला देश में सुना जाता है। हमारे देश की कुछ किताबों में छत्रपति शिवाजी को आतंकवादी के रूप में प्रस्तुत किया गया है। जब हम भारत की रक्षा करने वाले वीर शिवाजी को आतंकवादी के रूप में पढ़ेंगे, तब हमारी युवा पीढ़ी से हम किस प्रकार से यह अपेक्षा करें कि वे राष्ट्रीय स्वाभिमान के प्रति सजग रहें। इसी प्रकार जिन महापुरुषों ने देश को स्वतंत्र कराने के लिए बलिदान दिया, उनको पूरा सम्मान भी नहीं मिल रहा। उनको इतिहास की किताबों में भी नहीं पढ़ाया जा रहा है।

शिक्षा को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहली, किताबी शिक्षा तो दूसरी व्यावहारिक शिक्षा। किताबी शिक्षा के लिए आज भारत के शिक्षालय समर्पित दिखाई देते हैं। देश का हर निजी विद्यालय लगभग विदेशी शिक्षा से प्रभावित होकर अपने संस्थान में विदेश से प्रेरित शिक्षा देने का कार्य कर रहे हैं। जिसमें अंग्रेजी भाषा की प्रधानता तो है ही, साथ ही अंग्रेजी संस्कारों की बहुलता का दर्शन कराया जाता है। कौन नहीं जानता देश के ईसाई शिक्षा संस्थानों को, जिसमें प्रायः बच्चों को भारतीयता से दूर रखने का प्रयास किया जाता है। कई शिक्षा संस्थानों में इस बात के भी प्रमाण मिले हैं कि छात्रों को केवल ईसाई धर्म ही श्रेष्ठ है, इस प्रकार की शिक्षा दी जाती है। चर्च के रूप में संचालित किए जाने वाले ये ईसाई शिक्षा केंद्र आज भारत को नकारने जैसे ही कार्य करते दिखाई देते हैं। वहां भारत माता की जय बोलने पर प्रतिबंध होता है। कई बार छात्रों को भारत माता की जय बोलने पर दंडित किया जाता है। जिस शिक्षा के संस्थानों में उस देश के संस्कार नहीं होते, उस संस्थान की शिक्षा उस देश के विरोध में की गई कार्रवाई का ही हिस्सा माना जाता है।

वर्तमान में हमारे देश के सरकारी शिक्षण संस्थानों की हालत का अध्ययन करने से पता चलता है कि इन संस्थानों में छात्रों की उपस्थिति लगातार गिरती जा रही है। इसके पीछे का मूल कारण हमारी शिक्षा नीति को ही माना जा सकता है। आज केन्द्र की मोदी सरकार ने नई शिक्षा नीति लागू करके देश को एक ऐसे मार्ग पर ले जाने का प्रयास किया है, जिसकी वर्षों से प्रतीक्षा थी। समूचे देश में शिक्षा का भारतीयकरण होना ही चाहिए। यह भारत का दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि कुछ कुत्सित मानसिकता के लोगों द्वारा शिक्षा के भारतीयकरण को भगवाकरण का नाम दे दिया जाता है। भगवाकरण के नाम पर विरोध करने वाले वे ही लोग हैं, जो कथित बुद्धिजीवी बनकर देश की सरकारी सुविधाओं का भरपूर उपयोग कर रहे हैं। भारतीय शिक्षा का वास्तविक अर्थ यही है कि भारत से जुड़ी शिक्षा छात्रों को प्रदान की जाए। भारतीय मूल्यों के साथ रोजगारपरक शिक्षा सभी को मिले, तभी देश से बेरोजगारी जैसी समस्या का भी निर्मूलन हो सकेगा। साथ में अन्य क्षेत्रों में भी विकास तेजी से नजर आएगा।

हमें पहले यह समझना होगा कि शिक्षा किसलिए जरूरी है? क्या केवल साक्षर होने या नौकरी के लिए पढ़ाई की जानी चाहिए अथवा इसके और भी गहरे मायने हैं? विद्यालय, महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय वह केंद्र होते हैं, जहां विद्यार्थी को वैचारिक स्तर पर गढने का कार्य किया जाता है। सही बात यही है कि यदि प्रत्येक शिक्षण संस्थान के सभी प्रमुख अंग शिक्षक, शिक्षार्थी और गैर शैक्षणिक कर्मचारी अपने दायित्वों का निर्वहन सही तरीके से ईमानदार होकर करने लगें तो भारत में शिक्षा की साख पर उत्पन्न होते खतरे से आसानी से निपटा जा सकता है। जितना संभव हो उतना अधिक आर्थिक व अन्य सहयोग देश की शिक्षण संस्थाओं को दिया जाए।

पहले भारत की शिक्षा के प्रति विश्व के सभी देशों में एक आदर भाव था। विश्व के कई देशों के नागरिक भारत के शिक्षालयों में उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे, लेकिन आज के युवा विदेश में पढ़ाई करने के लिए उतावले होते जा रहे हैं। यह हमारी शिक्षा नीति का दुष्परिणाम ही कहा जाएगा। इस सबका परिणाम यह है कि भारतीय छात्रों में उत्तम किस्म की उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेशों के प्रति आकर्षण निरंतर बढ़ता जा रहा है। दुनिया के देशों के बीच आज भी भारत में उच्च शिक्षा में सबसे कम जनसंख्यात्मक अनुपात के हिसाब से प्रवेश होते हैं। उच्च शिक्षा की स्थिति बेहतर बनाने के लिए किए जा रहे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा राज्यों के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा लाख प्रयास किए जाने के बाद भी स्थिति में अभी तक बहुत सुधार नहीं आ पाया है। जैसी शिक्षा दी जाएगी, देश का मानस उसी प्रकार का बनता जाएगा। इसलिए समाज को इस प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए, जिससे असली भारत का निर्माण हो सके।

अवध की आवाज ब्यूरो

सीतापुर। अत्यंत दुखद ग्राम भन्डिया सिधौली, सीतापुर की घटना समुदाय विशेष के 4 लोगों के द्वारा एक मोर को लाठी डंडो से मारा और जब तक मोर मर नहीं गया तब तक पटक पटक कर मारते रहे, पुलिस को स्थानीय लोगों के द्वारा सूचना दी गई। जिसमें सलीम और मेराज पुलिस कि गिरफ्त मे है सिद्दू और किस्मत दो और पुलिस कि गिरफ्त से बाहर है, मृत मोर को पुलिस के द्वारा पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया।

अवध की आवाज ब्यूरो

उन्नाव। दिनांक 23.07.2021 को पुलिस अधीक्षक उन्नाव द्वारा पुलिस लाइन उन्नाव में परेड निरीक्षण उपरान्त नव निर्मित भवनों,सब्सडियरी कैन्टीन,भोजनालय तथा बैरिकों का निरीक्षण किया गया तथा सम्बन्धित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।

अवध की आवाज आम जन की आवाज गुड्डू मिश्रा ब्यूरो चीफ के साथ जिला स्वास्थ्य संवाददाता दीपक शुक्ला

लोकसभा ने ओलंपिक खेलों में भाग ले रहे भारतीय खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दीं

नई दिल्ली, (वेबवार्ता)। लोकसभा ने तोक्यो में आरंभ हुए 32वें ओलंपिक खेलों में भाग ले रहे भारतीय खिलाड़ियों के अच्छे प्रदर्शन और जीत की कामना की।

सदन की कार्यवाही आरंभ होने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन को सूचित किया कि इस बार के ओलंपिक खेलों में 127 भारतीय एथलीट भाग ले रहे हैं।

उन्होंने कहा, आज से ओलंपिक खेल आरंभ हुए हैं. ..इन खेलों में हमारे 127 एथलीट भाग ले रहे हैं जो अब तक की सबसे अधिक संख्या है। मैं अपनी ओर से और सदन की तरफ से इन खिलाड़ियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन करने और पदक जीतने की कामना करता हूं। गौरतलब है कि ओलंपिक खेलों की शुरुआत तोक्यो में हुई है। ओलंपिक में भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन लंदन ओलंपिक 2012 में था जब भारतीयों ने छह पदक जीते थे हालांकि एक भी स्वर्ण नहीं था।

ब्लैक फंगस से गंभीर रूप से पीड़ित सीतापुर निवासी रजनीश कुमार आरोग्यधाम के उपचार से ब्लैक फंगस बीमारी से हुए पूर्णतया स्वस्थ

सीतापुर से ब्लैक फंगस के गंभीर मरीज रजनीश कुमार सिंह आरोग्यधाम के चिकित्सकों का धन्यवाद करने पहुंचे कानपुर

होम्योपैथी में है ब्लैक फंगस एवं वायरल जनित बीमारियों का संपूर्ण उपचार

अवध की आवाज ब्यूरो

सीतापुर। सीतापुर निवासी 42 वर्षीय रजनीश कुमार सिंह (मो० नं० 9721063517) आज अपनी पत्नी एवं अपने भाई समेत ग्वालटोली स्थित आरोग्यधाम के चिकित्सक डॉ हेमंत मोहन एवं डॉक्टर आरती मोहन का धन्यवाद करने पहुंचे। आरोग्यधाम के वरिष्ठ होम्योपैथिक चिकित्सक डॉ हेमंत मोहन ने बताया की रजनीश कुमार सिंह जी को कोविड इंफेक्शन के अपने डेढ़ महीने लंबे उपचार के दौरान लखनऊ स्थित किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में भर्ती रहे। इलाज के दौरान इनका जबड़े एवं नाक का ऑपरेशन किया गया जिसके पश्चात इन्हें जबड़े में असहनीय दर्द एवं सांस लेने में परेशानी की समस्या हो गई थी जिसके इलाज के दौरान किसी ने इन्हें कानपुर स्थित आरोग्यधाम के चिकित्सकों के बारे में बताया। डॉ हेमंत मोहन से संपर्क करने पर डॉ हेमंत व डॉ आरती मोहन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भर्ती रहने के दौरान ही इन का होम्योपैथिक उपचार किया जिससे उन्हें काफी आराम मिला। डॉ आरती ने बताया की कोविड–19 के पश्चात ऑपरेशन होने के बाद जब इन्हें तकलीफ हुई तो इनके जबड़े एवं नाक की बायोप्सी की गई जिससे इन्हें ब्लैक फंगस इंफेक्शन की पुष्टि हुई। स्टेरॉयड एवं एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट लेने पर मरीज का शुगर लेवल बहुत तेजी से बढ़ता गया साथ ही हिमोग्लोबिन व सोडियम के लेवल में तेजी से कमी आ गई थी। जिसका होम्योपैथिक इलाज देने पर बहुत जल्द ही इन्हें आराम मिल गया। कोविड–19 के पश्चात रजनीश जी की शुगर बहुत तेजी से बढ़ गई की जिसका इंसुलिन थेरेपी द्वारा अभी भी इलाज चल रहा है । आरोग्यधाम के चिकित्सकों ने उन्हें जल्दी ही इंसुलिन से छुटकारा दिलाने का आश्वासन भी दिया एवं भविष्य में अच्छे स्वास्थ्य के लिए शुभकामनाएं प्रदान करें यह जानकारी जनहित में डॉ हेमंत व डॉ आरती मोहन ने दी।

टैंकर ने स्कूटी सवार दंपती को रौंदा, पत्नी की मौत, पति घायल

चंदौली। चंदौली जिले के अलीनगर थाना क्षेत्र के चकिया मोड़ के समीप शुक्रवार सुबह स्कूटी सवार दंपती को तेज रफ्तार टैंकर ने रौंद डाला। दर्दनाक हादसे में स्कूटी सवार महिला की मौके पर मौत हो गई। वहीं स्कूटी चला रहा पति घायल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बिहार के भभुआ थाना अंतर्गत भरीगावां निवासी सच्चिदानंद सिंह स्कूटी से अपनी पत्नी आरती देवी (56) के साथ वाराणसी के लंका जा रहे थे। वो जैसे ही चकिया मोड़ बाईपास पहुंचे कि पीछे से आ रहे एथेनॉल भरे टैंकर ने जोरदार टक्कर मार दी। टैंकर की चपेट मे आने से स्कूटी के पीछे बैठी आरती देवी की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वही टैंकर सहित चालक को लोगों ने पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। पुलिस टैंकर चालक को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है।

मिर्जापुर: ट्रैक्टर की टक्कर से जीप सवार युवक की मौत

मिर्जापुर जिले के हलिया थाना क्षेत्र के सेमरा चौराहा के पास ट्रैक्टर की टक्कर से जीप सवार एक युवक मौत हो गई वहीं चालक विजय (40) गंभरी रूप से घायल हो गया। घायल को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर उपजिलाधिकारी लालगंज अमित शुक्ला व प्रभारी निरीक्षक राजकुमार सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे।

पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक का नाम कलेक्टर (35) है। वह लालापुर में एक किसान के यहां ठेकेदारी पर श्रमिकों से धान की रोपाई करा रहा था। शुक्रवार को काम के सिलसिले में दिल्ली जाने वाला था। मृतक श्रमिक को दो पुत्र अरुण व करन तथा बेटी आंचल व काजल हैं। मौत की सूचना पर परिजनों में कोहराम मच गया है। सीओ उमाशंकर सिंह का कहना है ट्रैक्टर ट्राली व जीप को कब्जे में ले लिया गया है। इस संबंध में थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है।

अघोषित आपातकाल के जबड़े में फंस गया है देश- रामगोविंद चौधरी

लखनऊ। नेता प्रतिपक्ष, उत्तर प्रदेश रामगोविंद चौधरी ने कहा है कि अच्छे दिन के नाम पर यह महान देश अघोषित आपातकाल के जबड़े में फंस गया है। इसकी मुक्ति के लिए भारत समाचार टीवी और दैनिक भास्कर पर सरकारी हमले का विरोध ा कीजिए और इनका साथ दीजिए। शुक्रवार को मिलने आए साथियों से नेता प्रतिपक्ष रामगोविंद चौधरी ने कहा कि भारत समाचार टीवी के प्रध ाान सम्पादक ब्रजेश मिश्रा, कार्यकारी सम्पादक वीरेन्द्र सिंह और दैनिक भास्कर अखबार पर इनकमटैक्स का छापा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला है। अपने पापों से डरी हुई मोदी और योगी सरकार इन छापों के माध्यम से अपना अपना पाप छुपाने की कोशिश कर रही है। इससे डरने की जरूरत नहीं है। इससे टकराने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इसके पहले भी आपातकाल लगाकर देश की जनभावना को दबाने की विफल कोशिश हुई थी। इस बार अघोषित आपातकाल के माध्यम से यह कोशिश हो रही है। यह कोशिश भी सफल नहीं होगी।

नेता प्रतिपक्ष उत्तर प्रदेश रामगोविंद चौधरी ने कहा कि कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी से तड़प तड़प कर मरने वालों की चीख सुनकर पूरा देश रो पड़ा था। नदियों के तट लाशों से पट गए थे। भारत सरकार ने इसे लेकर एक प्रश्न के जवाब में लोकसभा में कहा है कि ऑक्सीजन की कमीं से देश में कोई नहीं मरा है। उसका आधार उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भेजा गया झूठ है।

उन्होंने कहा है कि भारत सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार चाहती

है कि मीडिया भी उसके इस झूठ को ही जनता के बीच सच के रुप में परोसे। बहुत से मीडिया हाउस परोस भी रहे हैं लेकिन जो नहीं परोस रहे हैं, जो ऑक्सीजन के अभाव में हुई मौतों के मामलों में सच बोल रहे हैं, वह भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के निशाने पर हैं।

नेता प्रतिपक्ष उत्तर प्रदेश रामगोविंद चौधरी ने कहा है कि पेगासस सॉफ्टवेयर के माध्यम से विपक्ष के प्रमुख नेताओं, मुख्य न्यायाधीश और पत्रकारों का फोन टेप कर की गई जासूसी के मामले भी यही स्थिति है। भारत सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार चाहती है कि इसे लेकर सभी मीडिया हाउस सरकार की अपराधिक साजिश का साथ दें। उन्होंने कहा कि इस मामले में किसी स्तर पर अब दो राय नहीं है कि फोन टेप कर जासूसी की गई है। इस साफ्टवेयर को बनाने वाले देश ने बता दिया है कि वह यह साफ्टवेयर केवल सरकार को बेचता है। इसलिए यह भी तय है कि इस मामले में सरकार दोषी है। अब जांच का विषय यह है कि इस जासूसी के बल पर सरकार ने किसे किसे किस स्तर पर ब्लैकमेल किया और कौन कौन सा पाप कराया। उन्होंने कहा कि फोन जासूसी के इस स्पष्ट मामले भी भारत सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार चाहती है कि मीडिया उनके पाप पर परदा डाले और उन दो जासूसों से इस मामले को नहीं जोड़े जो पूर्व में भी गुजरात में इस तरह की जासूसी कर चुके हैं।

नेता प्रतिपक्ष उत्तर प्रदेश रामगोविंद चौधरी ने कहा है कि आप सभी लोग एक सप्ताह के समाचारों पर नजर डालें तो लगेगा कि भारत समाचार टीवी और दैनिक भास्कर ने इन दोनों मामलों में सरकारों के दबाव को नहीं माना। जनता के समक्ष वही परोसा जो सच था। उन्होंने कहा है कि इसी वजह से इन दोनों मीडिया संस्थानों को डराने के लिए भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की देखरेख में इनकमटैक्स की रेड पड़ी है। यह कार्रवाई लोकतन्त्र के खिलाफ है, स्वराज की भावना के खिलाफ है, इसलिए इस कार्रवाई को किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करना है। ऐसे निष्पक्ष पत्रकारों और मीडिया का साथ देना है।

नेता प्रतिपक्ष उत्तर प्रदेश रामगोविंद चौधरी ने कहा है कि यह लोकतन्त्र और स्वराज हम लोगों को भारी कुर्बानी के बाद मिला है। इस लोकतन्त्र और स्वराज की रक्षा के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में हम लोग बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने को तैयार हैं। हम समाजवादी सरकार के जुल्म से डरने वाले नहीं हैं। इस भावना के साथ हम लोग निष्पक्ष मीडिया के साथ मजबूती से खड़े हैं। भारत समाचार टीवी के बहादुर प्रध ाान सम्पादक ब्रजेश मिश्रा और कार्यकारी सम्पादक वीरेन्द्र सिंह के साथ तो किसी स्तर तक।

नेता प्रतिपक्ष उत्तर प्रदेश रामगोविंद चौधरी ने कहा है कि महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और उत्पीड़न की वजह से भाजपा की सरकारें लोगों का विश्वास पहले ही खो चुकी हैं। इधर वोट के लिए हुए सरेआम चीरहरण, राफेल में दलाली और फोन जासूसी प्रकरण के बाद लोग भाजपा सरकारों से जल्द जल्द मुक्ति चाह रहे हैं। इसका ज्ञान राफेल की दलाली खाने वालों और वोट लूटने वालों को भी हो गया है। इसलिए इन सरकारों ने देश में अघोषित आपातकाल कायम कर रखा है। उन्होंने कहा है कि जो भी टीवी और अखबार लोगों की भावना को उजागर कर रहे हैं, सच बोल रहे हैं, इस अघोषित आपातकाल को नजरअंदाज कर रहे हैं, भाजपा की सरकारें उन्हें मिटा देने पर आमादा हैं। समाजवादी पार्टी भाजपा की इस कुत्सित कोशिश को किसी कीमत पर सफल नहीं होने देगी।

हर मंडल मुख्यालय पर बनेंगे सैनिक स्कूल- योगी आदित्यनाथ

गोरखपुर,। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि केंद्र सरकार ने इस बार के बजट में देश मे 100 नए सैनिक स्कूल खोलना प्रस्तावित कर रखा है। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए प्रदेश सरकार हर कमिश्नरी में सैनिक स्कूल खोलने की योजना पर तेजी से कार्य कर रही है। गोरखपुर में बनने जा रहा सैनिक स्कूल पूर्वी उत्तर प्रदेश के विद्यार्थियों को सैन्य प्रशिक्षण के साथ योग्यतम शिक्षा देने का प्रयास है। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि गोरखपुर के खाद कारखाना परिसर में सरकार स्किल डेवलपमेंट का बड़ा केंद्र भी खोलेगी। यहां प्रशिक्षण प्राप्त के लिए देश और दुनियां में कहीं भी बेहतर शर्तों पर रोजगार मिल सकेगा। सीएम योगी शुक्रवार को गोरखपुर खाद कारखाना परिसर में उप मुख्यमंत्री डॉ दिनेश शर्मा के साथ मिलकर सैनिक स्कूल का शिलान्यास कर रहे थे। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच भूमि पूजन कर विद्यालय की आध ाारशिला रखने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सैनिक स्कूल एक बड़ी उपलब्धि है। यहां पढ़ने वाले विद्यार्थियों को देश के कई क्षेत्रों में आगे बढ़ने, उच्च पदों पर सेवा करने का अवसर प्राप्त होगा। यहां के सैनिक स्कूल में अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सैनिक स्कूलों का अपना इतिहास है। प्रदेश में पहला सैनिक स्कूल 1960 में तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉ संपूर्णानंद ने स्थापित किया था। कारगिल विजय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले परमवीर चक्र विजेता शहीद कैप्टन मनोज पांडेय ने भी इसी सैनिक स्कूल से शिक्षण प्रशिक्षण प्राप्त किया था। 2017 में भाजपा की सरकार यूपी में आई तो सरकार ने लखनऊ सैनिक स्कूल का नामकरण शहीद कैप्टन मनोज पांडेय के नाम कर दिया। सीएम योगी ने कहा कि 1990 में खाद कारखाना बंद हो जाने के बाद 26 साल तक केंद्र व पिछली राज्य सरकारों ने यहां के खाद कारखाने की सुधि नहीं ली। 2016 में प्रध ाानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका नए सिरे से शिलान्यास किया। 2017 में यूपी में बीजेपी की सरकार आई तो खाद कारखाना परिसर विकास की गतिविधियों का केंद्र बन गया।

हाय सफेद बाल

–पूरन सरमा–

बाल सफेद होने का अब कोई मतलब नहीं रह गया है। पहले सफेद बाल व्यक्तित्व की पहचान हुआ करते थे। बाल सफेद होने पर आदमी को समझदार, शिष्ट तथा गरिमामय माना जाता था। राजा दशरथ ने एक बार कान के पास एक सफेद बाल देखा तो उन्होंने राजपाट छोड़ कर संन्यास की तैयारी कर ली थी। सफेद बालों की ही देन थी कि लोग संन्यासाश्रम एवं वानप्रस्थाश्रम में चले जाया करते थे, लंगोट लगा लेते थे। अब मामला उलटा है। सारे वे काम सफेद बालों के बाद होने लगे हैं जो काले बालों में किए जाते थे। 50 वर्ष की उम्र में भी बाल सफेद हों तो लोग इसे खानपान अथवा तेलादि का विकार मान कर शिष्टता धारण करने को ही तैयार नहीं हैं। उलटे मेहंदी लगा लेंगे, सैलून में डाई करा लेंगे तथा अन्य कई प्रकार के लोशन लगा कर सफेदी को छिपा लेंगे। ज्यादा समझाओ कि भाई, बाल सफेद हो गए, अब तो धैर्य धरो, तो कहेंगे कि बाल सफेद हो गए तो क्या, दिल तो अभी काला है।

यह सही है कि जब तक दिल काला रहेगा, बाल के सफेद होने का कोई अर्थ नहीं रहेगा। पहले के लोग ही मन से साफ होते थे और बाल सफेद होने के बाद तो और भी पावन हो जाया करते थे। घर में मुखिया के बाल ज्यों ही सफेद होने लगे कि वह संजीदगी ओढ़ कर साधु का आचरण करने लगता था। महल्ले के लोग ताऊ, बाबा अथवा बुड्ढा मान कर सम्मान दिया करते थे। उस की बात को तवज्जुह दी जाती थी। न्याय करने में ऐसे लोग पहल किया करते थे। उन की न्यायप्रियता प्रसिद्ध होती थी। अब देखिए, सफेद बालों की आड़ में काले कारनामे किए जाते हैं। सारी बेईमानियां इन की आड़ में करने का प्रयास किया जाता है। अब सफेद बालों वाले आदमी से ताऊ अथवा बाबा कह कर देखिए, उस से पहले उस की पत्नी आप से झगड़ लेगी। तुरंत बाजार जा कर बाल काले करने की दवा ले आएगी और सिर पर मलना शुरू कर देगी। वह नहीं चाहती कि उन पर असमय ह बुढ़ापा थोपा जाए। शरीर से बूढ़े हुए लोग मन से जवान रहने के कारण सफेद बालों की विशिष्टता को नकार रहे हैं। बाल सफेद होने की प्रक्रिया से अकेला पुरुष ही परेशान हो, ऐसा नहीं है, महिलाएं भी इन का नामोनिशान मिटा कर इन की खेती को समूल नष्ट करने की दिशा में जागरूक हैं। जो महिलाएं 40 की उम्र में बुढ़ापे के चिह्न शरीर पर आने पर अपना गौरव समझती थीं, अब देखिए, महिलाएं अपनी षष्टिपूर्ति के बाद भी इस फसल को सिर पर नहीं देखना चाहतीं। वे भी बालों को दवा, मेहंदी अथवा ब्यूटीपार्लर में जा कर काले करा रही हैं। सफेद बालों की यह समस्या दिनोंदिन विकट होती जा रही है। महिलाओं का सामान्यतया इस मामले में तर्क यह है कि यदि वे सफेद बालों को पनपने दें तो पुरुष उन की ओर देखना बंद कर देते हैं। कमोबेश रूप में यही स्थिति पुरुषों की है। वे भी 58 पार कर जाने के बाद भी यही चाहते हैं कि कोई हसीना उन पर भी एक न एक दिन नजर डालेगी, यदि उस समय उन के सिर पर बाल सफेद हुए तो सारा खेल बिगड़ जाएगा। इसलिए वे भी बाल रंग रहे हैं।

बालों का सफेद होना एक मनोवैज्ञानिक समस्या है, जिसे साइकोट्रीटमैंट की ही जरूरत है। इस में आदमी थोड़ा आत्मनियंत्रण नहीं रखे तो पागलपन तक की नौबत आ सकती है। अनेक लोग इन से त्रस्त हो कर अपना सिर नोंच डालते हैं तथा लहूलुहान हुए क्रोध ा में दांत पीसते रहते हैं। गोया बाल किसी पड़ोसी ने सफेद कर दिए हैं। यदि उस की उम्र के ही व्यक्ति के बाल काले हैं तो सफेद बाल वाले व्यक्ति की शंका की पुष्टि होने लगती है तथा वह टोनेटोटके द्वारा उस की शक्ति को क्षीण करने के उपाय भी करता है। धीरेधीरे मनोविकार बढ़ते जाते हैं तथा मैंटल केस के रूप में डैवलप होने लगते हैं। आपसी वैमनस्य, कुढ़न, कुंठा, घुटन, त्रासदी तथा आपराधिक भावनाएं परस्पर पनपती हैं तथा वातावरण विषाक्त होने लगता है। सफेद बाल वाले को काले बाल वाला फूटी आंख भी नहीं सुहाता। दिनोंदिन भीषण होती सफेद बालों की यह समस्या अपने समाधान के लिए मुंहबाए खड़ी है। यदि किसी के पास इस का बिना डाई के कोई समाधान हो तो मुझ से मिले, क्योंकि मेरे भी बाल सफेद होने की दिशा में तेजी से पहल कर रहे हैं। आप यह सोचते होंगे कि मैं वानप्रस्थ अथवा संन्यासाश्रम में प्रवेश कर जाऊंगा, यह तो मुझ से संभव है नहीं, बल्कि बाल सफेद होने के बाद तो गृहस्थाश्रम में मेरी रुचि बढ़ गई है, बस, थोड़ा सफेद बालों का मनोवैज्ञानिक दबाव मन पर सदैव बना रहता है।

एजीआर संबंधित बकाया की गणना में गड़बड़ी के आरोप संबंधी दूरसंचार कंपनियों की याचिका खारिज

नई दिल्ली, (वेबवार्ता)। उच्चतम न्यायालय ने वोडाफोन आइडिया और भारती एयरटेल समेत दूरसंचार क्षेत्र की बड़ी कंपनियों द्वारा समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) संबंधी बकाया की गणना में गलितयों का आरोप लगाते हुए दायर की गई याचिकाओं को शुक्रवार को खारिज कर दिया।

न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा, "सभी अर्जियां खारिज की जाती हैं।

दूरसंचार कंपनियों ने शीर्ष अदालत में दलील दी कि गणना में अंकगणितीय त्रुटियों को ठीक किया जाए और प्रविष्टियों में दोहराव के मामले भी हैं।

शीर्ष अदालत ने 19 जुलाई को कहा था कि वह दूरसंचार क्षेत्र की बड़ी कंपनियों द्वारा दायर आवेदनों पर आदेश पारित करेगी।

उच्चतम न्यायालय ने पिछले साल सितंबर में सरकार को अपनी बकाया राशि का भुगतान करने के लिए एजीआर से संबंधित 93,520 करोड़ रुपये का भुगतान करने के लिए संघर्ष कर रहे दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को 10 साल का समय दिया था।

प्रधानमंत्री मोदी ने तिलक, आजाद की जयंती पर उन्हें किया याद

नई दिल्ली, (वेबवार्ता)। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को स्वतंत्रता सेनानियों बाल गंगाधर तिलक और चंद्र शेखर आजाद को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की और देश के लिए उनके योगदान को याद किया। मोदी ने ट्वीट किया कि तिलक भारतीय मूल्यों तथा लोकाचार में दृढ़ विश्वास रखते थे और शिक्षा तथा महिला सशक्तिकरण पर उनके विचार कई लोगों को आज भी प्रेरित करते हैं। वह एक संस्था निर्माता थे और उन्होंने कई संस्थानों को अपनी सेवाएं दीं, जिन्होंने लगातार महान काम किए। उन्होंने कहा, " मैं महान लोकमान्य तिलक को उनकी जयंती पर नमन करता हूं। उनके विचार तथा सिद्धांत आज मौजूदा स्थिति में अधिक प्रासंगिक हैं, जब 130 करोड़ भारतीयों ने एक आत्मनिर्भर भारत बनाने का फैसला

किया है, जो आर्थिक रूप से समृद्ध और सामाजिक रूप से प्रगतिशील हो।"क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी आजाद को याद करते हुए मोदी ने कहा कि वह "भारत माता" के एक बहादुर पुत्र और एक उल्लेखनीय शख्स थे। उन्होंने कहा, " युवावस्था में उन्होंने भारत को साम्राज्यवाद के चंगुल से मुक्त कराने के काम में खुद को झोंक दिया। वह एक भविष्यवादी विचारक भी थे और एक मजबूत तथा निष्पक्ष भारत का सपना देखते थे।"औपनिवेशिक ब्रिटिश शासन के खिलाफ कई क्रांतिकारी आंदोलनों से जुड़े, आजाद ने कभी पुलिस द्वारा पकड़े नहीं जाने और "आजाद" रहने की कसम खाई थी। 1931 में एक मुठभेड़ में पुलिस द्वारा घेरे जाने पर 24 वर्षीय आजाद ने खुद को गोली मार ली थी। वहीं, 1856 में जन्मे, तिलक भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के अग्रणी नेता थे और उनकी 'स्वराज' की अवधारणा ने लोगों को काफी प्रभावित किया।

कृषि कानूनों को चालू सत्र में ही निरस्त करे केन्द्र सरकारः मायावती

लखनऊ, (वेबवार्ता)। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) सुप्रीमो मायावती ने केन्द्र सरकार से तीन कृषि कानूनों को चालू सत्र में ही रद्द करने की मांग की है। सुश्री मायावती ने शुक्रवार को कहा कि सरकार किसानो के प्रति अड़ियल रवैया अख्तियार कर रही है जो दुखःद है। कृषि कानूनों को लेकर किसान लंबे समय से आंदोलित है। सरकार को किसानो के हमदर्दी बरतते हुये कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला संसद के मानसून सत्र में ही करना चाहिये। उन्होने ट्वीट किया " किसानों के प्रति सरकारों को अहंकारी ना होकर बल्कि संवेदनशील व हमदर्द होना

चाहिए। किन्तु दुःख यह है कि तीन कृषि कानूनों को रद्द करने को लेकर काफी लंबे समय से किसान यहाँ आंदोलित है अब ये जंतरमंतर पर किसान संसद लगाए हैं केन्द्र चालू सत्र में ही इनको रद्द करें। बीएसपी की यह माँग।"

उन्नाव। जिला चिकित्सालय उन्नाव में ऑक्सीजन प्लांट लगने हेतु भूमि का निरीक्षण करते हुए जिलाधिकारी महोदय श्री रविंद्र कुमार साथ में मुख्य विकास अधिकारी महोदय दिव्यांशु पटेल।

अवध की आवाज हिन्दी दैनिक, प्रकाशक ,मुद्रक व स्वामी,अनिल कुमार सिंह द्वारा स्काई लाइन प्रिन्टर्स,119/23 खन्दारी लेन, लालबाग, लखनऊ उ0प्र0 से मुद्रित तथा डी–97/3 व 7,सेक्टर–7, इन्दिरा नगर,लखनऊ,उ0प्र0 से प्रकाशित। सम्पादक अनिल कुमार सिंह फोन : 0522–4340954 मो0–7905407289, Email: avadhkiaawaz@gmail.com
नोट : समाचार पत्र से सम्बंधित सारे विवादोंका न्याय क्षेत्र लखनऊ होगा।